

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिकी 336/2015

पंजीयन दिनांक 04.11.2015

- (1). राजेन्द्र कुमार पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (2). चन्द्रप्रकाश पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (3). यशवन्त कुमार पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (4). मजु पुत्री विजयसागर पत्नी सिद्धार्थ कुमार जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (5). आशा पुत्री विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (6). मंजुला बेवा स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (7). नीतू पुत्री स्वर्गीय योगेन्द्र कुमार जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांटगण

बनाम

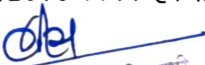
- (1). हमीद मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद मंसूरी निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (2). विजयसागर पिता भूरसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (3). ओमप्रकाश पिता विजयसागर जाति जती निवासी घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
- (4). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोंडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 132/2010 निर्णय एवं डिकी दिनांक 05.06.2015


राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

- उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांटगण
 (2). सम्पतलाल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1
 (3). रेस्पोजेन्टगण संख्या 2 व 3- अनुपस्थित
 (4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 4

निर्णय

दिनांक 18.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांटगण वादीगण ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं, अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 स्वर्गीय सूरसागर के वंशज हैं तथा सूरसागर का एकमात्र पुत्र रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर है। रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर के पांच पुत्र अपीलांटगण वादीगण संख्या 1 से 3, रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 एवं अपीलांटगण वादीगण संख्या 5 से 7 का पति एवं पिता योगेन्द्र कुमार हैं। योगेन्द्र कुमार की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस अपीलांट वादी संख्या 5 पत्नी, अपीलांट वादी संख्या 6 पुत्री व अपीलांट वादी संख्या 7 पुत्र हैं। मौजा घोसुण्डा की खाता संख्या 438 में दर्ज आराजी संख्या 1437, 1438, 1472 किता 3 रकबा 1.90 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो कि अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमें अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा निहित है। अपीलांटगण वादीगण एवं रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अपने-अपने हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं के नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाते हुए रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.05.1998 को उक्त आराजीयात विक्रय कर दी, उक्त विक्रयशुदा पैतृक कृषि आराजीयात में अपीलांटगण वादीगण व रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा निहित होने से रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था जिससे उक्त विक्रय पत्र अपीलांटगण वादीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। जिससे अपीलांटगण वादीगण उक्त वर्णित पैतृक कृषि आराजीयात में उक्त उनके निहित 6/8 हक हिस्से तक शून्य घोषित करा स्वयं



खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात का विक्रय के समय कोई विभाजन नहीं हुआ था जिससे बिना विभाजन कराये उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात को विक्रय करने का कोई अधिकार रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं था। यदि विक्रय पत्र को सही माना जावे तब भी रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 को स्वयं के निहित 1/8 हिस्से को ही विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। अन्त में अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विक्रय पत्र को अपीलांटगण वादीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य घोषित किया जाकर अपीलांटगण वादीगण को उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात में निहित उनके 6/8 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के 1/8 हिस्से एवं रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 के 1/8 हक हिस्से अनुसार उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात का के विभाजन की प्राथमिक डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया।



अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें वादपत्र में वर्णित तथ्यों की स्वीकारोक्ति की गई। रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वादपत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन किया गया। रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा स्वयं को फोरमल पक्षकार होना बताकर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया। दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प घोसुण्डा में रखी जाकर अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नहीं होना बताकर वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोजेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।


राजस्थान अपील विभाग

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 का जवाब प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 खारिज किये जाने का निवेदन किया व अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होना बताकर प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षकारान के अभिवचनो पर सुनवाई करते हुए व अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 व रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र पर का गहनता से अवलोकन व मनन किया।

न्यायाहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1967 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा स्वयं को फोरमल पक्षकार होना बताकर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2010 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.12.2010 नियत की गई। दिनांक 01.11.2011 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका में तनकियात कायम किया जाना अंकित है परन्तु पत्रावली में पर्चा तनकीयात उपलब्ध नहीं है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पत्रावली में तनकियात कायम किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार बिना तनकीयात कायम किये दिनांक 01.11.2011 की आदेशिका में तनकीयात कायम किया जाना बताकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई जिसके लिए तारीख पेशी 24.01.2012 नियत की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत रहते हुए दिनांक 25.05.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प घोसुण्डा में रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री



गुजरात उच्च न्यायालय

रत की है जो लोक अदालत की भावना क विपरीत होने व शिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांटगण वादीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019(1) पेज-291 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण वादीगण द्वारा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना बताकर उक्त वर्णित विवादित कृषि

आराजीयात की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु अपीलांटगण वादीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया गया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित नहीं होने से खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से प्रस्तुत

अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वक्त निर्णय सभी अपीलांटगण वादीगण उपस्थित होने के बावजूद अपीलांटगण वादीगण द्वारा अपील म्यांद बाहर प्रस्तुत किये जाने से निरस्त योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपील मेमो की कलम संख्या 4 वादपत्र मे वर्णित तथ्यों से हटकर होने के कारण अपील मे समाहित होने योग्य नहीं है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा पत्रक सम्वत 2042 भू-प्रबन्ध का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमे रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर व उसके पिता सूरसागर दोनो के नाम एक ही समय मे कृषि आराजीयात खातेदारी मे होना अंकित है। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर के नाम खातेदारी मे दर्ज आराजीयात का अपीलांटगण वादीगण की पैतृक सम्पत्ति होना साबित नहीं होकर रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 विजयसागर की स्वअर्जित सम्पत्ति होना प्रमाणित होता है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त कयशुदा आराजीयात का नामान्तरण रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्वीकृत होकर उक्त कयशुदा आराजीयात रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज हुई है। रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 कय दिनांक से ही उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र मे गवाह न0 1 के रूप मे विक्रेता के पुत्र रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षर है। साथ ही



राजस्व विभाग, जयपुर

वक्य अनुबंध दिनांक 23.03.1998 पर अपीलांगण वादीगण संख्या 1 से 3 एवं रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 के सहमति के रूप में हस्ताक्षर है जिससे ये सभी विबन्धन के सिद्धान्त से प्रतिबंधित है। पंजीकृत वक्य पत्र को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 का स्वयं की कयशुदा उक्त वर्णित आराजीयात पर सन 1998 से अर्थात् 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जा होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलांगण वादीगण रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने और घोषणा संबंधी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलांगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांगण वादीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।



राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांगण वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांगण वादीगण ने रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध कृषि आराजीयात की घोषणा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व उक्त पत्रावली में बिना तनकीयात कायम किये पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई। पत्रावली के साक्ष्य में विचाराधीन रहते हुए रेस्पोजेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना-पत्र आदेश 8 नियम 1 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जो बहस में विचाराधीन था। उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किये बगैर पत्रावली दिनांक 05.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत में नियत कर दी व बिना लिखित राजीनामे के अपीलांगण वादीगण जो लोक अदालत में उपस्थित हुए जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर बिना रेस्पोजेन्टगण प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज किये व उभय पक्षकारान के मध्य बिना लिखित राजीनामे के अपीलांगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नहीं मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपीलांगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019 पार्ट-1 पेज 291 इस प्रकरण पर चर्चा होने से अपीलांगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

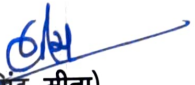
2019

राजस्वरूप अपील अपीलांतगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 132/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 8 नियम 1 जाफ़ा दीवानी का निस्तारण किया जाकर पत्रावली में दावे व जवाबदावे के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाफ़ा दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 19.09.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।




 (हरिसिंह मीना)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)
 चित्तौड़गढ़(राज0)